

**झारखंड उच्च न्यायालय, रांची**

**सिवल रिट न्यायिक न्यायालय संख्या 2382/1998**

1. जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, गया 72 - आंध्र प्रदेश, कॉलोनी, गया, थाना और जिला- गया
2. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, अरुणाचल भवन प्रदर्शनी रोड, पटना।
3. आंचलिक प्रबंधक (एफ) भारतीय खाद्य निगम, 10/ए, मिडलटन रो कलकत्ता -71 ..... याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. भारत संघ, द्वारा- श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. केन्द्रीय सरकार, श्रम न्यायालय नं. -II, धनबाद
3. विजयेंद्र कुमार एजी-द्वितीय (डिपो), भारतीय खाद्य निगम, जिला अधिकारी, गया-72 आंध्र प्रदेश, कॉलोनी, गया, थाना और जिला- गया ..... उत्तरदाताओं

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री निपुण बख्शी, अधिवक्ता

: श्री शुभम सिन्हा, अधिवक्ता।

भारत संघ के लिए : श्रीमती नीतू सिन्हा, अधिवक्ता।

उत्तरदाता के लिए : श्रीमती एम. एम. पाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

: श्रीमती मंजुश्री पात्रा, अधिवक्ता

: श्रीमती महुआ पालित, अधिवक्ता

**उपस्थित**

**माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी**

**अदालत द्वारा:-** दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.1997 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है, जो 1996 के श्रम न्यायालय आवेदन संख्या 15 में उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा पारित किया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी (2) के तहत दायर किया गया, जिसके तहत और जहां के तहत, श्रम न्यायालय ने माना कि उस मामले का आवेदक, आवेदक द्वारा दायर विस्तार डब्ल्यू -7 में रखे गए गणना चार्ट के अनुसार 28.12.1994 से 06.09.1996 तक वेतन और भत्तों की बकाया राशि की राहत के लिए हकदार है और रिट याचिकाकर्ताओं के प्रबंधन को निर्देश दिया जो श्रम न्यायालय के समक्ष विपक्षी पक्ष थे उक्त आदेश की तारीख से गणना के दो महीने के भीतर आवेदक द्वारा दी गई
3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि उत्तरदाता नंबर 3, जो 1996 के श्रम न्यायालय आवेदन संख्या 15 में केंद्र सरकार के श्रम न्यायालय नंबर 2, धनबाद के समक्ष याचिकाकर्ता था, एफसीआई कार्यकारी कर्मचारी संघ की राष्ट्रीय समिति के सचिव (कल्याण) होने के नाते एक संरक्षित कामगार था और उसे 23.03.1982 से निलंबित कर दिया गया था और केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण और उक्त न्यायाधीकरण के समक्ष पारित निर्णय 31.09.1990 निलंबन के खिलाफ केस संख्या 90/1990 में संदर्भ दिया गया था ने याचिकाकर्ताओं को आवेदक को सभी लाभ देने का निर्देश दिया। उसी के खिलाफ, सिवल रिट न्यायिक न्यायालय संख्या 1519/1991 को रिट याचिकाकर्ता द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जिसे आवेदक को सभी लाभ देने के निर्देश के साथ दिनांक 12.01.1994 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को दो अन्य व्यक्तियों के साथ कार्यालय आदेश भाग 1 संख्या 135/1996, दिनांक 14.08.1996 के तहत पदोन्नत किया गया था, जिसकी प्रति इस रिट याचिका के अनुलग्नक 2, पृष्ठ 39 पर रखी गई है। श्रम न्यायालय ने *अन्य बातों के साथ-साथ*

यह माना कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सिविल रिट न्यायिक न्यायालय संख्या 1519/1991 में, कामगारों की पदोन्नति की तारीख यानी 28.12.1994 से मजदूरी के बकाया भुगतान का आदेश दिया और उसी के साथ-साथ इसके समक्ष अन्य सामग्रियों के आधार पर, श्रम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33-सी (2) के तहत जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ता के के मामले में आवेदन की अनुमति दी।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से चार आधारों पर विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.08.1997 के आदेश का विरोध किया: -

(i) आक्षेपित अधिनिर्णय पर निर्णय लेने का पहला आधार यह है कि धारा 33-सी (2) के तहत कार्यवाही मूल रूप से निष्पादन कार्यवाही की तरह एक कार्यवाही है, विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा कोई अधिनिर्णय नहीं किया जा सकता था और इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील दिल्ली नगर निगम बनाम गणेश रजाक और एक अन्य (1995) 1 एससीसी 235 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसका पैरा 12 निम्नानुसार है:

"12. उच्च न्यायालय ने इनमें से कुछ फैसलों का उल्लेख किया है, लेकिन इसके सही महत्व से चूक गए। इन निर्णयों का अनुपात स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि *जहां दावे का आधार या एक निश्चित लाभ के लिए कामगारों की पात्रता विवादित है, नियोक्ता द्वारा पहले कोई अधिनिर्णय या मान्यता नहीं दी जा रही है, पात्रता से संबंधित विवाद दावा किए गए लाभ के लिए आकस्मिक नहीं है और इसलिए, अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत कार्यवाही के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर है। श्रम न्यायालय के पास पहले कामगारों की हकदारी का निर्णय लेने और फिर अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस आधार पर न्यायनिर्णयित लाभ की गणना करने के*

लिए आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह केवल तभी होता है जब नियोक्ता द्वारा पात्रता को पहले स्थगित या मान्यता दी गई हो और उसके बाद उसके कार्यान्वयन या प्रवर्तन के उद्देश्य से कुछ अस्पष्टता के लिए व्याख्या की आवश्यकता होती है कि व्याख्या को धारा 33-सी (2) के तहत श्रम न्यायालय की शक्ति के लिए आकस्मिक माना जाता है जैसे कि निष्पादन न्यायालय की शक्ति इसके निष्पादन के उद्देश्य के लिए डिफ्री की व्याख्या करने की शक्ति है। (महत्त्व सन्निविष्ट)

और इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील **बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम उप श्रम आयुक्त और अन्य (2022) 5 एससीसी 629** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा करते हैं, जिसका पैरा 10 निम्नानुसार है:

"10. इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करना, जब इस मुद्दे पर कोई पूर्व निर्णय नहीं था कि क्या उत्तरदाता 2 यहां एक विक्रेता के रूप में रोजगार में था जैसा कि उत्तरदाता द्वारा दावा किया गया था 2 यहां और एक गंभीर विवाद उठाया गया था कि उत्तरदाता 2 एक विक्रेता के रूप में रोजगार में कभी नहीं था और उत्तरदाता द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज 2 द्वारा गंभीर रूप से विवादित थे अपीलकर्ता और यह अपीलकर्ता की ओर से मामला था कि वे दस्तावेज जाली और/या झूठे हैं, इसके बाद श्रम न्यायालय को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत आवेदन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। श्रम न्यायालय को उत्तरदाता 2 को संदर्भ के माध्यम से उचित कार्यवाही शुरू करने और उसके अधिकार को क्रिस्टलीकृत करने और/या निर्णय लेने के लिए आरोपित करना चाहिए था।

जिसमें दिल्ली नगर निगम बनाम गणेश रजाक एवं अन्य के मामले में तय किए गए उपर्युक्त सिद्धांत को दोहराया गया है।

- ii. आक्षेपित पुरस्कार का समर्थन करने का दूसरा आधार यह है कि एक परिपत्र है, जिसे भारतीय खाद्य निगम के विस्तार एम 3 के रूप में चिह्नित किया गया है- जो खाद्य निगम अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक निगम है और इसके पास नियम और विनियमन बनाने की शक्तियां हैं, जिसके अनुसार, 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' सिद्धांत का पालन किया जाना है, लेकिन विद्वान श्रम न्यायालय इस पर विचार करने में विफल रहा है और वास्तव में, एक अधिनिर्णय किया, जो कानून में टिकाऊ नहीं है।
- iii. तीसरा आधार यह है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पदोन्नति के मामले में, 'नो वर्क, नो पे' सिद्धांत के बाद, बकाया का भुगतान नहीं किया जाना है और इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील, **भारत संघ और अन्य बनाम तरसेम लाल एवं अन्य (2006) 10 एससीसी 145** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं और अनुच्छेद 10 में रिपोर्ट किया गया, जिसके बारे में निम्नानुसार पढ़ा गया है:

*"10. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एक पीठ ने उस खंड को अमान्य माना लेकिन वीरेंद्र कुमार बनाम अविनाश चंद्र चड्ढा [(1990) 3 एससीसी 472: 1991 एससीसी (एल एंड एस) 62: (1990) 14 एटीसी 732: (1990) 2 एससीआर 769] में विचार को सही नहीं माना गया था। अब्राहम मामले में आदेश [1994 का सीए नंबर 8904 13- 8-1997 को फैसला किया गया] निम्नानुसार पढ़ता है:*

*"यह अपील केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एर्नाकुलम बेंच के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, ओए संख्या 649/90 दिनांक 30-9-1991 में। हालांकि अपील आदेश को पूरी तरह से चुनौती देती है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोस्वामी ने निष्पक्ष रूप*

से कहा कि अपील अब केवल न्यायधीकरण द्वारा दिए जाने वाले बकाया वेतन के भुगतान तक ही सीमित है।

अपील के तहत आदेश द्वारा, न्यायधीकरण ने उस आवेदन की अनुमति दी है जिसने रेलवे बोर्ड के परिपत्र दिनांक 15-9-1964/17-9-1964 को चुनौती दी थी। उक्त परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित खंड शामिल है:-

‘इस संबंध में कोई बकाया देय नहीं होगा क्योंकि उसने वास्तव में उच्चतर पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को वहन नहीं किया था।

‘उपर्युक्त खंड को हटाए जाने के परिणामस्वरूप, आगे के निर्देश दिए गए थे। विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि खंड, जिसे हटाने का निर्देश दिया गया है, वीरेंद्र कुमार बनाम अविनाश चंद्र चड्ढा [(1990) 3 एससीसी 472: 1991 एससीसी (एल एंड एस) 62: (1990) 14 एटीसी 732: (1990) 2 एससीआर 769] में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार है। इस न्यायालय ने, उस मामले में, ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर कहा कि उत्तरदाता उच्च वेतन के हकदार नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने वास्तव में उस पद पर काम नहीं किया है। अधिकरण द्वारा हटाए जाने का निदेश दिया गया खंड, इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप होने के कारण, हमारा विचार है कि अधिकरण ने उस खंड को हटाने का निदेश देकर सही नहीं किया था। तदनुसार, उस सीमा तक इस अपील को अनुमति दी जाती है। इसका परिणाम यह होगा कि प्रतिवादियों को सेवानिवृत्ति से पहले डीम्ड पदोन्नति, यदि कोई हो, दी जाएगी और पेंशन तय करने के मामले में भी लाभ दिया जाएगा। कोई लागत नहीं। (महत्व दिया गया)

- (iv) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत चौथा आधार यह है कि श्रम न्यायालय ने सिवल रिट न्यायिक न्यायालय संख्या 1519/1991 में माननीय

पटना उच्च न्यायालय के फैसले को गलत तरीके से उद्धृत किया है और मामले के तथ्यों में, यह असंभव है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस तरह का आदेश पारित कर सकता था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उनके पास सिविल रिट न्यायिक न्यायालय संख्या 1519/1991 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति नहीं है।

5. इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 22.08.1997 के आक्षेपित अधिनिर्णय को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।
6. दूसरी ओर, केंद्र सरकार के विद्वान वकील ने आक्षेपित पुरस्कार का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने सिविल रिट न्यायिक न्यायालय संख्या 1519/1991 में पारित माननीय पटना उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय/आदेश को प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन जैसा कि विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के अनुच्छेद 21 में इसका स्पष्ट संदर्भ नहीं दिया गया है, इसलिए इस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में, पदोन्नति की तारीख से बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए निर्देशित किया है, यानी 28.12.1994, रिट याचिकाकर्ताओं के लिए उपाय माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले के आदेश को उचित मंच पर चुनौती देना था, लेकिन निश्चित रूप से, केंद्र सरकार श्रम न्यायालय, 2 धनबाद के पास माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अधिलेखित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए, इसने माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का सही पालन किया है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि केंद्र सरकार के श्रम न्यायालय, 2, धनबाद में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है, इसलिए, यह रिट याचिका, योग्यता के बिना होने के कारण खारिज कर दी जाती है।
7. उत्तरदाता नंबर 3 के विद्वान वकील आक्षेपित आदेश का बचाव करते हैं और सीजीसी के लिए विद्वान वकील के तर्कों को अपनाते हैं।

8. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, इस अदालत ने पाया कि आक्षेपित आदेश के पैरा 21 में, विद्वान श्रम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सिवल रिट न्यायिक न्यायालय संख्या 1519/1991 में उत्तरदाता संख्या 3 को इस रिट याचिका की, जो विद्वान श्रम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता थी, उसकी पदोन्नति की तारीख यानी 28.12.1994 से मजदूरी की बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया है।
9. पूरी रिट याचिका को ध्यान से देखने के बाद, इस न्यायालय ने रिट याचिका में कहीं भी यह नहीं पाया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्देश का यह तथ्य सिवल रिट न्यायिक न्यायालय संख्या 1519/1991 में उत्तरदाता संख्या 3 को उनकी पदोन्नति की तारीख से यानी 28.12.1994 मजदूरी के बकाया भुगतान के लिए है, जो विद्वान श्रम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता था,; रिट याचिकाकर्ता द्वारा विवादित किया गया है। इस प्रकार यह तथ्यात्मक पहलू इसका संदर्भ माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुच्छेद 21 में किया गया है, जिसकी प्रति याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही रिट याचिका में कोई कथन है कि इस तरह के तथ्य कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सिवल रिट न्यायिक न्यायालय संख्या 1519/1991 में बकाया राशि के भुगतान के लिए निर्देश दिया है। इस रिट याचिका के उत्तरदाता संख्या 3, जो विद्वान श्रम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता थे, को उनकी पदोन्नति की तारीख यानी 28.12.1994 से, आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 21 में दिखाई देना, जिसे चुनौती दी गई है, झूठा है; यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की इस दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि श्रम न्यायालय द्वारा अपने आदेश के अनुच्छेद 21 में माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का ऐसा संदर्भ गलत है।
10. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय यह भी स्वीकार करता है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सिवल रिट न्यायिक न्यायालय संख्या 1519/1991 में ऐसा आदेश पारित किया है, जैसा कि आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 21 में संदर्भित है। इसलिए एक बार माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय हो जाने के बाद, निश्चित रूप से, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि विद्वान श्रम न्यायालय ने खुद को स्थगित कर दिया है, या उस मामले के लिए, इसने भारतीय खाद्य



निगम के परिपत्र पर विचार नहीं किया है, जिसे विस्तार एम 3 के रूप में चिह्नित किया गया था। जहां तक 'काम नहीं, वेतन नहीं' सिद्धांत के विवाद का संबंध है, कि एक विशिष्ट मामले में, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका के उत्तरदाता संख्या 3 को बकाया मजदूरी के भुगतान का एक विशिष्ट आदेश पारित किया है, 28.12.1994 को उनकी पदोन्नति की तारीख से, इसलिए निश्चित रूप से, यदि रिट याचिकाकर्ता इस तरह के आदेश से व्यथित हैं, जैसा कि सीजीसी द्वारा सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश को एक उचित मंच के समक्ष चुनौती दी होगी, लेकिन याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया है; निश्चित रूप से माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त निर्विवाद निर्णय पर भरोसा करने में विद्वान श्रम न्यायालय के आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, जो अंतिम रूप से पहुंच गया है और उन पर कार्रवाई करते हुए, एक आदेश पारित करने के बजाय, माननीय पटना उच्च न्यायालय के विपरीत, कानून के किसी भी सामान्य सिद्धांत का हवाला देते हुए स्कोर पर भी, इस न्यायालय को याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलील में कोई दम नजर नहीं आता।

11. इस अदालत को इस याचिका में और ऊपर की गई चर्चाओं में कोई योग्यता नहीं मिलती है, तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।
12. इस निर्णय की एक प्रति संबंधित न्यायालय को निचली अदालत के अभिलेखों के साथ तुरंत भेजी जाए।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची  
दिनांकित -12 दिसम्बर, 2023  
स्मिता / ए. एफ. आर.

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।